www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 217 नागपुर, सोमवार, 3 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

जीएसटी का विरोध आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमिलनाडु थिएटर

चेन्नई

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने का विरोध कर रहे करीब 1,100 थियेटरों में आज सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा 30 फीसद टैक्स लगाने के साथ ही 30 जून की मध्यरात्रि से लागू होने वाले जीएसटी के बाद थियेटर मालिकों को 18 फीसद जीएसटी देना होगा यानि कुल 48 फीसद टैक्स का भुगतान करना होगा।

स्थानीय थियेटर के अनुसार यह नया दर उनके कारोबार को प्रभावित करेगा। स्थानीय थियेटर के मैनेजर रामासामी ने कहा, जीएसटी के तहत सरकार की ओर से 18 फीसद का कर लगेगा और नगरनिगम ने 30 फीसद कर लगाया है यानि अब कुल मिलाकर 48 फीसद टैक्स भरना होगा। यह काफी अधिक है और हम इस टैक्स के साथ अपना कारोबार नहीं चला सकते।

तमिलनाडु थियेटर ने रविवार से टिकटों की एडवांस बुकिंग रोकने का निर्णय लिया है और अगले हफ्ते थियेटरों में कोई शो नहीं दिखाया जाएगा। इसके माध्यम से फिल्म थियेटर संघ निगम के टैक्स की वापसी की मांग कर रहा है। सोमवार को फिल्म उद्योग द्वारा भी प्रदर्शन किए जाने की संभावना है।

तमिलनाडु फिल्म प्रॉड्यूसर्स काउंसिल के अध्यक्ष विशाल ने बताया कि निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री समेत हर इंडस्ट्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र व वित्तमंत्री से उन्होंने क्षेत्रीय फिल्मों के लिए सबसे कम स्लैब उसके बाद गैर क्षेत्रीय फिल्म और सबसे अधिक स्लैब में विदेशी भाषाओं वाली फिल्मों को रखने की मांग की है।

पाक में कुलभूषण के लिए भारतीय वकील को मिले अनुमति - उज्जवल निकम

उदयपुर

विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम के अनुसार पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय वकील को अनुमति दी जानी चाहिए। निकम ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के समक्ष भारत की ओर से इस बात की शिकायत की जानी चाहिए की पाकिस्तान में जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराने की अनुमति मिले। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि लाहौर बार एसोसिएशन इस बात को कहने के लिए पर्याप्त है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में न्यायिक मुकदमा या न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अनुसार हमें अंतरराष्ट्रीय अदालत से पहले शिकायत करनी चाहिए कि जाधव को पाकिस्तान में भारतीय वकील का प्रतिनिधित्व मिले जो भारत की ओर से की गयी उचित मांग होगी । उनकी यह प्रतिक्रिया भारत द्वारा पाकिस्तान से जाधव के लिए राजनयिक पहुंच का अनुरोध किए जाने के बाद आयी है। विदेश मंत्रालय ने बताया, भारतीय नागरिक हामिद नेहाल अंसारी और कूलभूषण जाधव के लिए हमने फिर पाकिस्तान से राजनयिक पहुंच देने का आग्रह किया है। अप्रैल में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट की ओर से जासूसी व संदिग्ध गतिविधि के लिए मृत्युदंड दिया गया था। जाधव की इस सजा के खिलाफ भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत में पहुंचा। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने 18 मई को भारतीय नागरिक जाधव को फांसी देने पर रोक लगा दिया।

स्विस बैंकों में जमा धन: भारत 88वें स्थान पर फिसला, ब्रिटेन टॉप पर

नई दिल्ली

स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। वहीं ब्रिटेन पहले पायदान पर बना हुआ है। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के ताजा आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारतीयों द्वारा रखा गया धन विदेशी ग्राहकों के स्विस बैंकों में रखे कोष का केवल 0.04 प्रतिशत है। काले धन की समस्या के समाधान के लिये स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के लिये नये मसौदे से पहले ज्यूरिख स्थित एसएनबी ने यह आंकड़ा जारी किया। एसएनबी के इन आंकड़ों में इस बात का जिक्र नहीं है कि भारतीयों, प्रवासी भारतीयों या विभिन्न देशों की इकाइयों के नाम पर अन्य ने कितना-कितना धन जमा किया हुआ है।

बैंकों में जमा धन मामूली रूप से बढ़कर 2016 में 1,420 अरब स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) हो गयी जो इससे पूर्व वर्ष में 1,410 अरब स्विस फ्रैंक थी।

देश के हिसाब से देखा जाए तो स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे है। वहां के नागरिकों की जमा राशि 359 अरब स्विस फ्रैंक (25 प्रतिशत) हैं।

अमेरिका 177 अरब स्विस फ्रैंक (14 प्रतिशत) के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा किसी अन्य देश की हिस्सेदारी दहाई अंक में नहीं है। शीर्ष 10 देशों में वेस्ट इंडीज, फ्रांस, बहमास, जर्मनी, गुएर्नसे, जर्सी, हांगकांग तथा लक्जमबर्ग हैं। भारत 67.6 करोड़ स्विस फ्रैंक (करीब 4,500 करोड़ रुपये) के साथ 88वें स्थान पर है।

लगातार तीन साल गिरावट के बाद यह रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर आ गया हैं प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह 0.04 प्रतिशत रहा जो 2015 में 0.08 प्रतिशत था। पाकिस्तान 1.4 अरब स्विस फ्रैंक के साथ 71वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों में रूस 19वें स्थान (15.6 अरब स्विस फ्रैंक), चीन 25वें (9.6 अरब डालर), ब्राजील 52वें (2.7 अरब डालर) तथा दक्षिण अफ्रीका 61वें (2.2 अरब स्विस फ्रैंक) स्थान पर है।

2004 में भारत इस मामले में 37वें स्थान पर था

भारत 2015 में 75वें स्थान पर जबकि इससे पूर्व वर्ष में यह 61वें स्थान पर था। वर्ष 2007 तक स्विस बैंकों में विदेशियों के जमा धन के मामले में शीर्ष 50 देशों में शामिल था। वर्ष 2004 में भारत इस मामले में 37वें स्थान पर था।

स्विट्जरलैंड में बैंकिंग गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक अभियान के बाद ऐसी धारणा है कि जिन भारतीयों ने अपना अवैध धन पूर्व में स्विस बैंकों में रखा था, वे उन्हें दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर सकते हैं।

काले धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच स्विस बैंकों ने यह भी कहा कि सिंगापुर तथा हांगकांग जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों की तुलना में भारतीयों के स्विस बैंकों में कुछ ही जमा राशि हैं।

स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे

दुनिया भर के विदेशी ग्राहकों का स्विस

पीएम मोदी से हमारे विचार भिन्न, फिर भी रिश्तों पर नहीं पड़ा असर - राष्ट्रपति

नई दिल्ली

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा मैं पीएम मोदी की प्रसंशा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमने मिलजुलकर काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारे विचार भिन्न है, मगर फिर भी हमारे रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ा। रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किताब विमोचन के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोल रहे थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का साथ मिला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि प्रणब दा की अंगुली पकड़ कर दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को स्थापित करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति के साथ काम करने का अवसर मिला।

मेरा मकसद है कि हम एक समाज के तौर पर इतिहास को जान सकें और उसके लिए जागरुक हों और अपने इतिहास के अहम पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। पीएम ने कहा कि मुझे इमर्जेंसी के दौरान अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला।

जीएसटी से गरीबों को फायदा, भ्रष्टाचार होगा खत्म - योगी

वाराणसी

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी के दौरे पर थे। उन्होंने ककरहिया गांव मे बने नन्द घर का निरीक्षण कर सबसे पहले पारिजात पेड़ रोपित किया और उसके बाद बच्चों को निशुल्क स्कूली बैग किट बाटें व महिलाओं को सोलर चरखा विरतण किया। मुख्यमंत्री के 5 मिनट के लिए ककरहिया आने की सूचना से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार 100 दिन विश्वास के कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी से गरीबों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जहां जितनी कम बिजली चोरी होगी वहां उतनी ज्यादा बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए योगी ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानती है। यूएस के राष्ट्रपति भी मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ककहरिया गांव में आयोजित समारोह में घोषणा करते हुए कहा कि वाराणसी के ककहरिया गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की राजनीतिक में अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। समाज की समस्या का समाधान जातिवाद और परिवारवाद नहीं बल्कि समाजिक न्याय है। यह सरकार प्रदेश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भ्रष्टाचार से घिरे अफसरों की जानकारी सार्वजनिक करें

नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों से घिरे अधिकारियों से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। पारदर्शिता निगरानी संस्था ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सरकारी अफसर के संख्यात्मक आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि उनके नामों को सार्वजनिक नहीं करने को कहा है। सूचना आयुक्त यशोव्रद्धन आजाद ने कहा है, किसी भी परिस्थिति में, आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।

पीओके नेता बोले, हमारी जमीं पर आतंकियों को भेजना बंद करे पाक सरकार व सेना

हजिरा

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थानीय लोगों व नेताओं ने पाक सरकार और सेना के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया है। उनका आरोप है कि आतंकी कैंप स्थापित कर पीओके को एक टेरर फैक्ट्री बनाया जा रहा है। हजिरा निवासी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि आतंकयों को उनके क्षेत्र में सुरक्षित जगह देकर पाक सरकार व सेना द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आने वाले दिनों में पीओके में इस विरोध-प्रदर्शन के और व्यापक होने के आसार हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस क्षेत्र में अब भी करीब 50 आतंकी प्रशिक्षण कैंप संचालित हैं और इनमें अधिकतर लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झांगवी और आइएसआइएस जैसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। इन कैंपों को पाक सेना और इंटर सर्विस इंटेलीजेंस द्वारा समर्थन व मदद भी मिल रहा है। यहां आतंकियों को प्रशिक्षित कर कश्मीर, अफगानिस्तान और यहां तक कि यूरोप भी भेजा जाता है। जेकेएनएपी के वरिष्ठ नेता लियाकत हयात खान ने कहा, हम हाथ जोड़कर पाक सेना और पीएम से अनुरोध करते हैं कि यहां आतंकी ना भेजें। सभी धर्मों के लोग यहां की शांतिपूर्ण धरती पर रहते हैं। ऐसी जगहों पर बम धमाके कराए जा रहे हैं, जहां हिंदू और शिया दोनों पूजा करते हैं।

जब उपभोक्ता जीएसटी से परेशान नहीं हैं, तो व्यापारी क्यों शोर मचा रहे हैं - जेटली

नई दिल्ली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आश्चर्य जताया कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं, जबकि कराधान का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जेटली ने कहा कि माल व सेवा कर के बारे में उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं।

कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है

उन्होंने कहा कि पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उचित टैक्स बास्केट बनाने की कोशिश की है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं? व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है।

वित्तमंत्री ने कहा कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है।

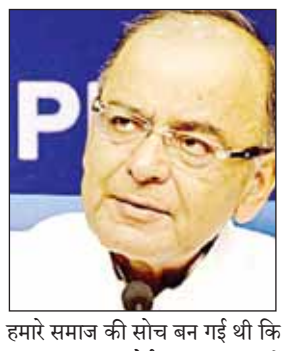

हमारे समाज की सोच बन गई थी कि कर न चुकाना कोई गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नई सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए।

आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो

उन्होंने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गई तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है।

उन्होंने कुछ आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 फीसदी की श्रेणी को मिलाकर एक श्रेणी बनाई जा सकती है।

यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है

उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम 15 फीसदी की एक दर से जीएसटी लागू करेंगे तो टैक्स छूट वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी, जिनका इस्तेमाल गरीब भी करते हैं। यह सही नहीं होगा। मालूम हो कि जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 फीसदी टैक्स की चार दर तय की गई हैं। जेटली ने कहा कि यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और इसे रह राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ लोग चिंतित हैं, इसलिए वे इससे दूरी बनाकर चल रहे हैं।

लालू - नीतीश के बीच और गहराई खाई

'बीजेपी हटाओ देश बचाओ' रैली से जदयू का किनारा !

पटना

लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 27 अगस्त 2017 को बीजेपी के विरोध में बिहार में एक बड़ी रैली रखी है, जिससे सत्तारूढ़ सरकार जेडी (यू) के किनारा करने के आसार नजर आ रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि रैली आरजेडी ने रखी है और जदयू उसमें पार्टी के तौर पर शामिल नहीं होने वाली। श्याम ने आगे बताया कि अगर नीतीश कुमार को रैली में शामिल होने का कोई न्योता मिलेगा तो वह सोचेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें शामिल होना है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जेडी(यू) के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को न्योता दिया जाता है तो वह निजी तौर पर उसमें उपस्थित होने के बारे में फैसला लेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वह राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार की जगह एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। नीतीश ने यह भी कहा था कि विपक्ष ने बिहार की बेटी (मीरा कुमार) को हारने के लिए खड़ा किया है। इतना ही नहीं जीएसटी लॉन्च के लिए हुए कार्यक्रम में नीतीश ने अपनी और से प्रतिनिधि भेजा था। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। जानकारी मुताबिक इस रैली कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा इस रैली में शामिल हो सकते हैं।

मारपीट और मुकदमे के भय से तनाव में रहते हैं 82.7 फीसदी डॉक्टर

डॉक्टरों से ऑनलाइन सवाल-जवाब के आधार पर किए गए सर्वे में 1681 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया

नई दिल्ली

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाओं के मद्देनजर सर्वे किया है, जिसके नतीजे चिकित्सक दिवस (डॉक्टर्स डे) के दिन शनिवार को जारी किए गए।

सर्वे में यह बात सामने आई है कि मारपीट की घटनाओं के कारण डॉक्टरों में डर बढ़ रहा है। उन्हें मारपीट व मुकदमेबाजी का भय सताता है। सर्वे में 82.7 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने काम को लेकर तनाव में रहते हैं।

1681 डॉक्टरों ने लिया भाग

यह सर्वे डॉक्टरों से ऑनलाइन सवाल-जवाब के आधार पर किया गया है। इसमें

1681 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। आईएमए ने सर्वे को नतीजों को बेहद गंभीर बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि सर्वे के नतीजों से स्पष्ट है कि चिकित्सा का पेशा मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

चिकित्सकों के मन में हर वक्त भावनात्मक व शारीरिक हमले का डर सताता रहता है। यह चिकित्सा जगत के लिए ठीक नहीं है। सर्वे के दौरान 46.3 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे हिंसा के कारण तनाव में रहते हैं।

24.2 फीसदी डॉक्टरों को मुकदमे का डर रहता है और 13.7 फीसदी डॉक्टरों को आपराधिक मामला चलाए जाने की चिंता बनी रहती है। सिर्फ 36.8 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने पेशे से पूरी तरह खुश हैं। 38.5 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ हद तक ही अपने पेशे से संतुष्ट हैं। 24.7 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने पेशे से खुश नहीं हैं। 56 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी व्यस्तताओं के कारण सात घंटे की नींद भी नहीं ले पाते। 62.8 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों के इलाज के दौरान भी उन्हें मारपीट की चिंता सताती है।

32 फीसदी बेटे-पोते को नहीं बनाना चाहते डॉक्टर

32.3 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने बेटे व पोते को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते। हालांकि 60.9 फीसदी डॉक्टरों ने कहा कि बेटे या पौत्र अपने भविष्य के बारे में फैसला खुद करेंगे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे।

आईएमए ने पहले भी अस्पतालों में मारपीट की घटनाओं पर सर्वे किया था। इसमें यह बात सामने आई थी कि अस्पतालों में ज्यादातर मारपीट की घटनाएं इलाज में देरी के कारण होती हैं।

मनमोहन सिंह की तुलना में कम विदेशी दौरे पर रहे पीएम मोदी - अमित शाह

पणजी

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने विदेशी दौरे मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना में तीन साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कम विदेशी दौरे किए हैं। पणजी में निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान शाह ने यह बात कही और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि पीएम मोदी के विदेशी दौरे को लेकर लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों है।

अमित शाह ने बताया कि एक भाजपा कार्यकर्ता ने इसके पीछे के कारण का उल्लेख किया। पार्टी कार्यकर्ता ने मुझसे कहा जब मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तब कोई नहीं जान पाता था। मनमोहन सिंह की आलोचना

करते हुए शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे पर लिखित भाषण को पढ़ा करते थे। वे अपने साथ अंग्रेजी में लिखे गए भाषण को लेकर चलते थे और उसे पढ़ने के बाद लौट आते थे। कभी कभी मलेशिया के लिए तैयार भाषण को थाइलैंड में पढ़ दिया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे की तुलना करते हुए शाह ने कहा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान दुनिया को यह पता नहीं होता था कि भारतीय प्रधानमंत्री इस वक्त चीन, अमेरिका या रूस के दौरे पर हैं।

लेकिन, अब जब मोदी चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग जमा हो जाते हैं और पूरी दुनिया को यह पता चल जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा पर हैं।